March-August 1979, had severe repurcussion on Industrial Production. Unless credit policy is liberalised production will be severely hampered.

(b) The Federation felt that the very first requirement was the restoration of normal production conditions.

(c) and (d). In the Minimum Programme the Federation had suggested several remedial measures including those for checking inflation. Government is determined to keep prices under reasonable control and suggestions in this regard from various quarters including the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry are given due consideration. Anti-inflationary measures taken by the Government have been discussed in the Economic Survey 1979-80 recently presented to Parliament and further measures wil be taken as and when necessary in the light of emerging trends.

Production of Stainless Steel

3050. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Centre has decided to increase the licensed capacity of existing steel rolling mills in the country for production of stainless steel;

(b) if so, whether any guidelines have been prepared by the Ministry in this regard;

(c) if so, what are the details of the guidelines issued;

(d) what will be increased in capacity of production of stainless steel;

(e) whether the All India Small Scale Stainless Steel Rollers Association has urged Government to put a total ban on the import of stainless steel sheets; and

(f) if so, whether they have submitted any memorandum to the Prime Minister in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

(e) Yes, Sir.

(f) Yes, Sir. They submitted a memorandum on this subject to the Prime Minister of India on 15th May, 1980.

Import of Rubber

3051. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have authorised to import 10,000 tonnes of rubber;

(b) if so, whether Government are also considering to allow further import to be affected in 1980-81 to meet the gap between demand and supply;

(c) if so, what is the total demand and supply anticipated during 1980-81;

(d) whether any charges have been made to give direct benefit to the actual users;

(e) what are the new norms proposed; and

(f) whether it is also a fact that a delegation in this regard had met the Prime Minister recently and had urged her not to allow import of rubber to India?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Import of 10,000 tonnes of rubber was authorised in January, 1980. A quantity of 400 tonnes was imported against this authorisation and further imports stayed.

(b) Import of rubber is considered on a periodical review of the demand-supply position and price structure and imports restrict to minimum requirement.

(c) For 1980-81, the estimated demand for rubber is 185,000 tonnes and the estimated supply is 155,000 to 160,000 tonnes.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) Yes, Sir.

गैर योजना व्यय में कमी

3052. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गैर योजना व्यय कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है और इसको किस प्रकार से व्यवहारिक रूप दिया गया है; और

(ख) इस वर्ष गैर योजना व्यय कितना रहा है और विभिन्न विभागों द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट): (क) और (ख). दो विवरण पत्र संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण-पत्र-1

गैर विकासात्मक व्यय में कमी करने के लिये सरकार द्वारा किफायत के संबंध में अपनाये गये उपायों का ब्यौरा

पिछले अनेक वर्षों में सरकार के गैर विकासात्मक व्यय मे किफायत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है। मई, 1977 में मंत्रालयों/विभागों को किफायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय करने के लिये कहा गया था :--

(1) विद्यमान कर्मचारी संख्या मे कम से कम 10% की कमी करने पर विचार करें;

(2) अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों और नियमक क्रिया-कलापों का यह पता लगाने के लिये समीक्षा करें कि उनमें से कोई क्रिया-कलाप अनावश्यक हो गये है और उनको लोकहित अथवा अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को हानि पहुंचाये बिना समाप्त किया जा सकता है;

(3) विद्यमान प्रणालियों और कार्यविधियों की जांच की जाये ताकि कार्यकुशलता को नुकसान पहुंचाये बिना दोहरे काम को समाप्त किया जा सके।

(4) जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई है और इस समय विद्यमान है उन सभी के बारे में यह पता लगाने के लिये विस्तृत जांच की जाए कि उनसे कोई महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है जो उनका आगे बना रहना न्यायोचित ठहराता हो; और

(5) मौजूदा कानूनों की जांच की जाए क्योंकि हो सकता है, समय गुजरने और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ उनमें से कुछ कानून निष्प्रयोजन हो गये हों; ताकि ऐसे कानूनों को निरधित किया जा सके और उनके प्रशासन के लिये मूलत: भर्ती किये गये कर्मचारियों को वापस भेजा जा सके।

2. 1979 में मंत्रालयों/विभागों को यह भी सलाह दी गई कि:--

(क) आयोजना-भिन्न पद में, कोई अतिरिक्त पद तब तक मन्जूर नही किये जाने चाहिए जब तक कि अन्य पदों को वापिस करके बराबर राशि की बचत न की गई हो, सिवाये पूर्णतया नये संगठनों के मामले मे, जिनके लिये आवश्यकता को विशेष रूप से स्वीकार किया गया हो;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये जो पद स्वीकृत किये गये थे उनकी संख्या मे भारी कांट-छांट करने के लिये पुनरीक्षण किया जाना चाहिए; और

(ग) विदेशों में प्रतिनियुक्तियों पर और प्रतिनिधिमंडलों की संख्या मे भारी कटौती की जानी चाहिये।

3. 1979 में मंत्रालयों/विभागों को और आगे यह कहा गया है कि कागज के इस्तेमाल गैर हकदार श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा के मामले में किफायत करने और अधिकारियों के कार्यालय तथा